Non-Payment of Bnifead and Interest by Companies

1442. SHRI V. HANUMANTHA RAC Mil the PRIME MINISTER be pleasec to state:

(a) whether Government are aware that many small investors are not getting their dividends or interest payments from many companies;

(b) if so, what safeguards for small shareholders are available; and

(c) whether the Ministry of Finance would monitor such companies in the interest of small investors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Government have received complaints agaist some companies regarding delay in payment of dividend, non-refund of share application money or non-payment of interest on delayed refund and non-payment or delayed payment of interest on debentures and fixed deposits.

(b) and (c) Sufficient safeguards are available under Sections 73 and 207 of the Companies Act in regard to non-refund, or non payment of interest on delayed refund, of share or debenture application money and delay in payment of dividend. The Companies Bill, 1993 contains provisions empower, ing the Company Law Board to order payment of interest on debentures and interest on fixed deposits. The Bill also contains a provision prohibiting companies which have defaulted in payment of fixed deposits ot interest thereon from inviting/renewing deposits. Complaints received from investors are taken up with concerned companies for redressal and prosecutions are also filed in appropriate cases.

Bifurcation of Delhi subordinate Judiciary

1443. SHRI V. GOPALSAMY :
SHRI SHIV PRATAP MISHRA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to Unstarred Question 4342 given in the Rajya Sabha on the 26th August, 1993 and state:

(a) whether Government are aware of the demand that the subordinate judiciary in Delhi should be bifurcated; and

(b) if so, whether Government, have bifurcated the courts in Delhi :

(c) if not, whether Government are considering decentralisation of courts in Delhi ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS : (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) The modalities of bifurcation of the Delhi District Courts is receiving the Government attention in consultation with National Capital Territory of Delhi and the High Court.

(c) and (d) The Chief Justice of Delhi High Court has been requested to apprise the Government of the view of the Delhi High Court on the subject. A reply is awaited.

महिलाओं पर अत्याचार

1444. श्री मूलचन्द मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) इन मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) मामले, विभिन्न जटिल कारणों से लंबित हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन 4 दिसम्बर, 1993 को आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत

किये गए संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है। न्याय-प्रशासन को मामलों को शीघ्र निपटाये जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से एक योजना भी बनाया गया है।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालय के अधीन राज्य	लंबित मामलों की सं० (31-10-1992 का यथा-विद्यमान)
1. आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	203
2. मुंबई	(i) महाराष्ट्र (ii) गोवा (iii) दमन और दीव (iv) दादरा और नागर हवेली	431
3. कलकत्ता	(i) पश्चिमी बंगाल (ii) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	382 (31-12-1992 को यथा-विद्यमान)
4. दिल्ली	दिल्ली	146 (31-12-1992 को यथा-विद्यमान)
5. गुवाहटी	(i) असम (ii) मणिपुर (iii) त्रिपुरा (iv) मिजोरम (v) नागालैंड (vi) अरुणाचल प्रदेश (vii) मेघालय	कुछ नहीं
6. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	81
7. जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर	9
8. कर्नाटक	कर्नाटक	70
9. केरल	(i) केरल (ii) लक्षद्वीप	36
10. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	311
11. मद्रास	तमिलनाडु	17
12. पटना	बिहार	60
13. उड़ीसा	उड़ीसा	1
14. राजस्थान	राजस्थान	1331 (26-2-1994 को यथाविद्यमान)
15. सिक्किम	सिक्किम	कुछ नहीं

टिप्पणी:—इलाहाबाद, गुजरात और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों ने पहले सूचना दी थी कि उनके द्वारा ऐसे मामलों का कोई पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता है।